भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *109
दिनांक 29 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

देश में कुपोषण की समस्या

***109. श्रीमती फुलो देवी नेतामः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 की चरण 1 की रिपोर्ट के अनुसार 16 राज्यों में सामान्य से कम वजन वाले बच्चों की संख्या में बढोतरी होने और 12 राज्यों में अत्यधिक क्षीणकाय बच्चों की संख्या में बढोतरी होने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत केवल 112 आकांक्षी जिलों को ही लक्षित किए जाने के क्या कारण है जबकि अल्पपोषण और कुपोषण की समस्या केवल इन्हीं जिलों तक सीमित नहीं है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2021-20 में मिशन पोषण 2.0 के बजट में वर्ष 2020-21 में पूर्ववर्ती योजनाओं, जिन्हें विलय कर दिया गया था, के लिए आंबटित बजट की तुलना में 18.5 प्रतिशत की कटौती की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

'देश में कुपोषण की समस्या' के संबंध में श्रीमती फुलो देवी नेताम द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2021 को राज्यसभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 109 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) : पोषण संकेतकों संबंधी आंकड़े स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आवधिक रूप से संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के तहत संग्रहीत किए जाते हैं। एनएफएचएस-4 वर्ष 2015-16 में और एनएफएचएस-5 वर्ष 2019-20 में संचालित किया गया। एनएफएचएस-4 और एनएफएचएस-5 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनेपन, दुबलेपन और अल्पवज़न का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। एनएफएचएस-5 की हाल ही में जारी रिपोर्ट केवल 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में उपलब्ध है।

बाल पोषण सूचकांकों जैसे अत्यधिक दुबलेपन और ठिगनेपन जो पुरानी प्रकृति के हैं, की स्थिति में भारी बदलाव कुछ समय के अंतराल में होना संभव नहीं है। एनएफएचएस-5 के तहत दी गई सूचना के अनुसार, सर्वेक्षण दौरों के बीच 4 वर्षों के छोटे अंतराल के बावजूद बहुत से राज्यों की पोषण स्थिति में सुधार हुआ है। इसके अलावा, पोषण संकेतकों के सभी एनएफएचएस-5 बिंदु अनुमान विश्वास अंतराल के भीतर आते हैं और अधिकांश राज्यों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया है।

(ख) : कुपोषण कम करने और 0-6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में समयबद्ध तरीके से सुधार हासिल करने के उद्देश्य से **देश भर में** 08 मार्च, 2018 को पोषण अभियान की शुरूआत की गई थी।

बजट 2021-2022 में घोषित मिशन पोषण 2.0 (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) स्वास्थ्य, कल्याण और रोग तथा कुपोषण से प्रतिरक्षा पोषित करने वाली पद्धतियां विकसित करने पर बल देने सहित पोषण सामग्री, प्रदायगी, पहुंच और परिणामों को सशक्त बनाने का एक समेकित पोषण सहायता कार्यक्रम है। मिशन 2.0 का 5 वर्षों (2021-22 से 2025-26) के लिए अनुमोदन किया गया है और इसमें आंगनवाड़ी सेवाएं (पूरक पोषण कार्यक्रम-एसएनपी), किशोरी स्कीम और पोषण अभियान नामक पोषण केंद्रित उप-स्कीमों को फिर से बनाया गया है।

मिशन पोषण 2.0 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों और आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु की किशोरियों सहित लाभार्थियों को लक्षित किया जाएगा।

(ग) और (घ) : वर्ष 2020-21 के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरी स्कीम सहित स्कीमों के लिए बजट आबंटन 24,482 करोड़ रुपये था। वर्ष 2021-22 में युक्तिकरण के बाद, इन तीनों स्कीमों को संयोजित करके 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' नाम दिया गया है जिसका बजटीय प्रावधान 20,105 करोड़ रुपये है। देशभर में आंगनवाड़ी सेवाओं के कार्यान्वयन और निगरानी पर रीयल टाईम डाटा एकत्र करने के लिए पोषण ट्रैकर नामक एक सशक्त आईसीटी युक्त प्लेटफार्म तैयार किया गया है। यह आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और अन्य लाभार्थियों की गहन निगरानी करने में सहायक होगा। आवश्यकता पड़ने पर संशोधित अनुमान चरण में वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधियों की मांग की जाएगी।

*****

अनुलग्नक-I

'देश में कुपोषण की समस्या' के संबंध में श्रीमती फुलो देवी नेताम द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2021 को पूछे जाने वाले राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या 109 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

ठिगनापन, दुबलापन और अल्पवज़न (एनएफएचएस-4 और एनएफएचएस-5)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ठिगनापन		दुबलापन		अल्पवज़न	
		एनएफएचएस-4	एनएफएचएस-5	एनएफएचएस-4	एनएफएचएस-5	एनएफएचएस-4	एनएफएचएस-5
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23.3	22.5	18.9	16	21.6	23.7
2	आंध्र प्रदेश	31.4	31.2	17.2	16.1	31.9	29.6
3	असम	36.4	35.3	17	21.7	29.8	32.8

4	बिहार	48.3	42.9	20.8	22.9	43.9	41
5	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	37.2	39.4	26.7	21.6	35.8	38.7
6	गोवा	20.1	25.8	21.9	19.1	23.8	24
7	गुजरात	38.5	39	26.4	25.1	39.3	39.7
8	हिमाचल प्रदेश	26.3	30.8	13.7	17.4	21.2	25.5
9	जम्मू और कश्मीर	27.4	26.9	12.2	19	16.6	21
10	कर्नाटक	36.2	35.4	26.1	19.5	35.2	32.9
11	केरल	19.7	23.4	15.7	15.8	16.1	19.7
12	लक्षद्वीप	30.9	30.5	9.3	17.5	18.7	20.4
13	लद्दाख	26.8	32	13.7	17.4	23.6	25.8
14	महाराष्ट्र	34.4	35.2	25.6	25.6	36	36.1
15	मेघालय	28.9	23.4	6.8	9.9	13.8	13.3
16	मणिपुर	43.8	46.5	15.3	12.1	28.9	26.6
17	मिजोरम	28.1	28.9	6.1	9.8	12	12.7
18	नागालैंड	28.6	32.7	11.3	19.1	16.7	26.9
19	सिक्किम	29.6	22.3	14.2	13.7	14.2	13.1
20	तेलंगाना	28	33.1	18.1	21.7	28.4	31.8
21	त्रिपुरा	24.3	32.3	16.8	18.2	24.1	25.6
22	पश्चिम बंगाल	32.5	33.8	20.3	20.3	31.6	32.2
23	अरुणाचल प्रदेश	29.4	-	17.3	-	19.4	-
24	चंडीगढ़	28.7	-	10.9	-	24.5	-
25	छत्तीसगढ	37.6	-	23.1	-	37.7	-
26	दिल्ली	31.9	-	15.9	-	27	-
27	हरियाणा	34	-	21.2	-	29.4	-
28	झारखंड	45.3	-	29	-	47.8	-
29	मध्य प्रदेश	42	-	25.8	-	42.8	-
30	ओडिशा	34.1	-	20.4	-	34.4	-
31	पुद्दुचेरी	24	-	23.8	-	22.7	-
32	पंजाब	25.7	-	15.6	-	21.6	-
33	राजस्थान	39.1	-	23	-	36.7	-
34	तमिलनाडु	27.1	-	19.7	-	23.8	-
35	उत्तर प्रदेश	46.3	-	17.9	-	39.5	-
36	उत्तराखंड	33.5	-	19.5	-	26.6	-